राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3706/2004

दिलीप सिंह यादव पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम: खानपुर डांगरान, तहसील: कोटकासिम, जिला। अलवर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से राजस्थान राज्य को।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर।
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, कोटकासिम, अलवर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : कोई मौजूद नहीं
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री गोपाल कृष्ण शर्मा-अतिरिक्त जीसी
श्री उत्तम झाझरिया और के साथ
श्री सौरव यादव

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

<u>07/10/2024</u>

समाचार-योग्य

1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के खिलाफ 18.09.1982 से उसे वरिष्ठता प्रदान करने का निर्देश मांग रहा है।

2. वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ निर्धारित करने के लिए, 18.09.1982 से प्रभावी, याचिकाकर्ता द्वारा 22 वर्षों के बाद वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के कथनों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने दो दशकों से अधिक समय तक चुप्पी क्यों बनाए रखी और 22 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद और अन्य प्रभावित व्यक्तियों को कारण शीर्षक की श्रेणी में पक्षकार बनाए बिना वह क्यों जागा।

3. चार दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, अन्य व्यक्तियों की वरिष्ठता को भंग नहीं किया जा सकता। पुराने दावों को उठाने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करने का कानून इतना स्थापित है कि इस पर बहस करना मुश्किल है और जहाँ पुराने दावे लंबे समय से स्थापित वरिष्ठता को चुनौती देने या उस पर विवाद करने से संबंधित हों, वहाँ न्यायालयों का हमेशा से यही मानना रहा है कि लंबे समय से स्थापित वरिष्ठता को भंग

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, न्यायिक मिसालों का भंडार है, हालाँकि, मैं **शिबा शंकर महापात्रा एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य, (2010) 12 एससीसी 471** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दे सकता हूँ, जिसमें इस पहलू पर पहले के कई फैसलों का ज़िक्र किया गया है और संबंधित अंश इस प्रकार हैं:-

> "18. लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिका पर विलंब से विचार करने का प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने रामचंद्र शंकर देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1974) 1 एससीसी 317: 1974 एससीसी (एल एंड एस) 137] में पदोन्नति और वरिष्ठता सूची को चुनौती देने में देरी के प्रभाव पर विचार किया और यह माना कि विलंब से वरिष्ठता का कोई भी दावा खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह वरिष्ठता, पद और पदोन्नति के संबंध में अन्य व्यक्तियों के निहित अधिकारों को बाधित करना चाहता है जो उन्हें बीच की अवधि के दौरान प्राप्त हुए हैं। किसी पक्ष को शिकायत का कारण ज्ञात होने के तुरंत बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उक्त मामले का फैसला करते समय, इस न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों पर भरोसा किया, खासकर तिलोकचंद मोतीचंद बनाम एच.बी. मुंशी [(1969) 1 एससीसी 110] में, जिसमें यह देखा गया है कि जिस सिद्धांत के आधार पर न्यायालय राहत देने से इनकार करता है याचिकाकर्ता को लापरवाही या देरी के आधार पर जो राहत मिली है, वह यह है कि रिट याचिका दायर करने में देरी के कारण दूसरों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण न हो। न्यायालय ने आगे निम्नलिखित टिप्पणी की: (तिलोकचंद मामला [(1969) 1 एससीसी 110], एससीसी पृष्ठ 115, पैरा 7)
>
> > "7. ... मौलिक अधिकारों का दावा करने वाले पक्ष को अन्य अधिकारों के अस्तित्व में आने से पहले न्यायालय में आवेदन करना होगा। यदि न्यायालय में आवेदन करने वाले व्यक्ति की ओर से देरी के कारण निर्दोष पक्षों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो न्यायालय की कार्रवाई निर्दोष पक्षों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती।"
>
> 19. इस न्यायालय ने रामचंद्र शंकर देवधर मामले [(1974) 1 एससीसी 317: 1974 एससीसी (एल एंड एस) 137] में रवींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ [(1970) 1 एससीसी 84] में संविधान पीठ के अपने पहले के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया है: (रवींद्रनाथ बोस मामला [(1970) 1 एससीसी 84], एससीसी पृष्ठ 97, पैरा 33)
>
> > "33. ... प्रतिवादियों को उनके प्राप्त अधिकारों से वंचित करना अन्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचने का अधिकार होना चाहिए कि बहुत समय पहले की गई उनकी नियुक्ति और पदोन्नति कई वर्षों के बीत जाने के बाद रद्द नहीं की जाएगी।"
>
> 20. आर.एस. मकाशी बनाम आई.एम. मेनन [(1982) 1 एससीसी 379 : 1982 एससीसी (एल एंड एस) 77] में इस न्यायालय ने कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में रिट याचिका दायर करने में सीमा, विलंब और लापरवाही के सभी पहलुओं पर विचार किया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई [एआईआर 1964 एससी 1006] में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि विधानमंडल द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि,

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

जिसके भीतर किसी दीवानी न्यायालय में किसी मुकदमे में राहत प्राप्त की जानी चाहिए, को सामान्यतः एक उचित मानक माना जा सकता है जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार प्राप्त करने में होने वाले विलंब को मापा जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (आर.एस. मकाशी मामला [(1982) 1 एससीसी 379: 1982 एससीसी (एल एंड एस) 77], एससीसी पृ. 398-400, पैरा 28 और 30)

> "28. … '33. … हमें कानून और समता, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांतों के अनुसार न्याय करना चाहिए। प्रतिवादियों को उनके प्राप्त अधिकारों से वंचित करना अन्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बैठकर विचार करे कि बहुत समय पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति कई वर्षों के बीत जाने के बाद रद्द नहीं की जाएगी। …' [संपादक: जैसा कि रवींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ, (1970) 1 एससीसी 84, पृष्ठ 97, अनुच्छेद 33 में कहा गया है।]
>
> * * *
>
> 30. … याचिकाकर्ताओं ने 1968 के सरकारी प्रस्ताव में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के खिलाफ चुनौती के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने में अपनी ओर से हुए अत्यधिक विलंब के लिए कोई भी वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया है। … हम तदनुसार यह मानेंगे कि 22-3-1968 के सरकारी प्रस्ताव में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा विलंब और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था और रिट याचिका को, जहां तक वह उक्त सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की प्रार्थना से संबंधित थी, खारिज कर दिया जाना चाहिए था।"

21. वरिष्ठता सूची को चुनौती देने का मुद्दा, जो लंबे समय से अस्तित्व में था, इस न्यायालय द्वारा के.आर. मुद्गल बनाम आर.पी. सिंह [(1986) 4 एससीसी 531: 1987 एससीसी (एल एंड एस) 6: एआईआर 1986 एससी 2086] में फिर से विचार किया गया। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया: (एससीसी पृ. 532 और 536, पैरा 2 और 7)

> 2. … किसी भी पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी को सामान्यतः नियुक्ति के कम से कम 3 या 4 वर्ष बाद अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन शांतिपूर्वक तथा बिना किसी असुरक्षा की भावना के करने की अनुमति दी जानी चाहिए। …
>
> * * *
>
> 7. … संतोषजनक सेवा शर्तें यह मानती हैं कि सरकारी कर्मचारियों में कई वर्षों के बाद दायर की गई रिट याचिकाओं से उत्पन्न अनिश्चितता की भावना नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इस मामले में हुआ। यह आवश्यक है कि जो कोई भी अपनी वरिष्ठता से व्यथित महसूस करता है, उसे यथाशीघ्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, अन्यथा सरकारी कर्मचारियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होने के अलावा, प्रशासनिक जटिलताएँ और कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होंगी। … इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को लापरवाही के आधार पर खारिज करना गलत था।"

(महत्व जोड़ें)

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

22. के.आर. मुद्गल मामले [(1986) 4 एससीसी 531: 1987 एससीसी (एल एंड एस) 6: एआईआर 1986 एससी 2086] पर निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने मैल्कम लॉरेंस सेसिल डिसूजा बनाम भारत संघ [(1976) 1 एससीसी 599: 1976 एससीसी (एल एंड एस) 115: एआईआर 1975 एससी 1269] में अपने पहले के फैसले पर भरोसा रखा, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया था: (सेसिल डिसूजा मामला [(1976) 1 एससीसी 599: 1976 एससीसी (एल एंड एस) 115: एआईआर 1975 एससी 1269], एससीसी पृष्ठ 602, पैरा 9)

> "9. यद्यपि सेवा की सुरक्षा को किसी लोक सेवक की चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर भी लोक सेवाओं में संतुष्टि और दक्षता की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक सुरक्षा की भावना है। निस्संदेह, इसके सभी विविध पहलुओं में ऐसी सुरक्षा की गारंटी देना कठिन है, लेकिन कम से कम यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि वरिष्ठता सूची में किसी व्यक्ति की स्थिति जैसे मामले, एक बार तय हो जाने के बाद, कई वर्षों के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर फिर से न खोले जाएँ जिसने बीच की अवधि में चुप रहना चुना हो। वरिष्ठता जैसे पुराने मामलों को लंबे समय के बाद उठाने से प्रशासनिक जटिलताएँ और कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए, सेवा की सुचारुता और दक्षता के हित में यह प्रतीत होता है कि ऐसे मामलों को कुछ समय बीत जाने के बाद शांत कर दिया जाना चाहिए।"

(महत्व जोड़ें)

23. बी.एस. बाजवा बनाम पंजाब राज्य [(1998) 2 एससीसी 523: 1998 एससीसी (एल एंड एस) 611] में इसी तरह के मुद्दे पर फैसला करते समय इस न्यायालय ने उसी दृष्टिकोण को दोहराया, जैसा कि नीचे दिया गया है: (एससीसी पृष्ठ 526, पैरा 7)

> "7. ... यह सर्वमान्य है कि सेवा मामलों में वरिष्ठता के प्रश्न को उचित अवधि बीत जाने के बाद दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि इससे स्थापित स्थिति बिगड़ सकती है जो न्यायोचित नहीं है। वर्तमान मामले में ऐसी शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ। केवल यही कारण अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप को अस्वीकार करने और रिट याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त था।"

(महत्व जोड़ें)

24. दयाराम ए. गुरसाहनी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 3 एससीसी 36: 1984 एससीसी (एल एंड एस) 341] में, इसी तरह के विचार को दोहराते हुए इस न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पूछताछ में 8-9 वर्षों की अत्यधिक देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, अन्य कर्मचारी को सौंपी गई वरिष्ठता और पदोन्नति की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता।

25. पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य [(1975) 1 एससीसी 152 : 1975 एससीसी (एल एंड एस) 22] में इस न्यायालय ने उस मामले पर विचार किया जहाँ पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका चौदह वर्ष बीत जाने के बाद दायर की गई थी। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पीड़ित व्यक्ति को राहत के लिए शीघ्र ही न्यायालय का रुख

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

करना चाहिए और बिना किसी पूर्व दावे के दावा प्रस्तुत करना उचित नहीं है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 154, पैरा 2)

> "2. … किसी कनिष्ठ को उसके ऊपर पदोन्नति देने के आदेश से व्यथित व्यक्ति को कम से कम छह महीने या अधिकतम एक वर्ष के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।"

न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालयों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोई सीमा अवधि है, न ही ऐसा कोई मामला हो सकता है जहाँ न्यायालय एक निश्चित अवधि के बाद किसी मामले में हस्तक्षेप न कर सकें। न्यायालयों के लिए यह अधिकार क्षेत्र का एक उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होगा कि वे अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग उन व्यक्तियों के मामले में करने से इनकार कर दें जो राहत के लिए शीघ्रता से न्यायालय से संपर्क नहीं करते हैं और जो चुपचाप खड़े होकर घटनाओं को घटित होने देते हैं और फिर पुराने दावे पेश करने और तयशुदा मामलों को उलझाने की कोशिश करने के लिए न्यायालय का रुख करते हैं।

26. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा सुदामा देवी बनाम कमिश्नर [(1983) 2 एससीसी 1]; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज बहादुर सिंह [(1998) 8 एससीसी 685: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 252] और नॉर्दर्न इंडियन ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम जसवंत सिंह [(2003) 1 एससीसी 335] में दोहराया गया है।

27. दिनकर अन्ना पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1999) 1 एससीसी 354: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 216] में इस न्यायालय ने माना कि वरिष्ठता को चुनौती देने में देरी और लापरवाही हमेशा घातक होती है, लेकिन यदि पक्षकार देरी के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट कर देता है, तो मामले पर विचार किया जा सकता है।

28. के.ए. अब्दुल मजीद बनाम केरल राज्य [(2001) 6 एससीसी 292: 2000 एससीसी (एल एंड एस) 955] में इस न्यायालय ने माना कि किसी भी कर्मचारी को दी गई वरिष्ठता को सात वर्ष बीत जाने के बाद इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित थी, हालाँकि गुण-दोष के आधार पर भी यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सही ढंग से निर्धारित की गई थी।

29. यह स्थापित कानून है कि आदेश के समापन के बाद, तटस्थ पक्षकारों को विवाद उठाने या उसकी वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी पक्षकार अधिकार के रूप में राहत का दावा नहीं कर सकता क्योंकि राहत देने से इनकार करने का एक आधार यह है कि न्यायालय में आने वाला व्यक्ति विलंब और लापरवाही का दोषी है। लोक विधि क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय उन पुराने दावों को बढ़ावा नहीं देता जहाँ तीसरे पक्ष के अधिकार अंतराल में स्पष्ट हो जाते हैं। (देखें अफलातून बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल [(1975) 4 एससीसी 285: एआईआर 1974 एससी 2077]; मैसूर राज्य बनाम वी.के. कंगन [(1976) 2 एससीसी 895: एआईआर 1975 एससी 2190]; नगर परिषद, अहमदनगर बनाम शाह हैदर बेग [(2000) 2 एससीसी 48]; इंद्रजीत गुप्ता बनाम भारत संघ [(2001) 6 एससीसी 637: 2001 एससीसी (एल एंड एस) 1083]; शिव दास बनाम भारत संघ [(2007) 9 एससीसी 274: (2007) 2

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

एससीसी (एल एंड एस) 395]; ए.पी. एसआरटीसी बनाम एन. सत्यनारायण [(2008) 1 एससीसी 210: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 161] और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम दोसु आर्देशिर भिवंडीवाला [(2009) 1 एससीसी 168])।

30. इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्थापित कानूनी प्रस्ताव उभर कर आता है कि एक बार वरिष्ठता तय हो जाने और एक उचित अवधि तक अस्तित्व में रहने के बाद, उस पर किसी भी चुनौती पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। के.आर. मुद्गल मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया है कि यदि वरिष्ठता सूची 3 से 4 वर्षों तक बिना किसी चुनौती के अस्तित्व में रहती है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वरिष्ठता को चुनौती देने के लिए 3-4 वर्ष एक उचित अवधि है और यदि कोई इस अवधि के बाद वरिष्ठता के मुद्दे पर आंदोलन करता है, तो उसे न्यायिक मंच पर जाने में हुई देरी और लापरवाही के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।

4. डॉ. अक्षय बिसोई एवं अन्य बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य (2018) 3 एससीसी 391 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी लाभदायक होगा, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:-

"19. वर्तमान मामले में न्यायालय के समक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें अतिरिक्त प्रोफेसर के पद पर भर्ती 2005 में की गई थी। यह 12 वर्ष से भी अधिक समय पहले की बात है। याचिकाकर्ताओं ने चयन समिति द्वारा 12-9-2005 को दिए गए रैंकिंग क्रम पर सवाल उठाने के लिए नवंबर 2017 में अनुच्छेद 32 के तहत यह कार्यवाही शुरू की है। कानूनी उपायों का इस विलंबित सहारा लेने का कोई ठोस कारण नहीं है। याचिकाकर्ता केवल यह तर्क देकर अपनी ओर से हुई देरी को वैध रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते कि वे प्रथम प्रतिवादी को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए प्रस्तुत कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने सद्भावपूर्वक यह विश्वास किया होगा कि एम्स प्रशासन उनकी शिकायतों पर ध्यान देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। लेकिन बारह वर्ष किसी भी तरह से न्यायिक उपायों का सहारा न लेने के लिए बहुत लंबा समय है। जैसा कि तथ्यों के विवरण से संकेत मिलता है, शासी निकाय ने 14-4-2012 को योग्यता क्रम को बनाए रखने का निर्णय लिया था जिसके अनुसार चौथे प्रतिवादी को दोनों से ऊपर प्रथम स्थान दिया गया था। याचिकाकर्ताओं। इसके बाद भी, अक्टूबर 2012 में शासी निकाय द्वारा एक तीन-सदस्यीय समिति गठित की गई और 19-7-2013 को एक बार फिर वरिष्ठता क्रम को बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इसे 12-5-2014 और 22-6-2016 को दोहराया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई सुसंगत स्थिति से अवगत थे। कानूनी उपायों का सहारा लेने में उनकी ओर से की गई देरी उनके विरुद्ध होनी चाहिए। इस स्तर पर, 2005 में चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश को फिर से खोलकर सीटीवीएस विभाग के तीन प्रोफेसरों के बीच आपसी वरिष्ठता को अस्थिर करना स्पष्ट रूप से अनुचित होगा।

20. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अप्रत्याशित देरी उन्हें राहत पाने के अधिकार से वंचित कर देगी, हम उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी [उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी, (2013) 12 एससीसी 179 : (2014) 3 एससीसी (एल एंड एस) 32] मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने, इस संबंध

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

में कानून की स्थापित स्थिति पर विचार करते हुए, यह टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 185-86, अनुच्छेद 27-28)

> "27. हम पूरी तरह से जानते हैं कि इस मामले में पदोन्नति संवर्ग में वरिष्ठता को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है और किसी भी पदोन्नति को रोका नहीं जा सकता। ... प्रतिवादियों ने रिप वैन विंकल की तरह सोना चुना और अपनी नींद से अपनी मर्ज़ी से उठे, किसी ऐसे कारण से जो केवल उन्हें ही समझ में आता है। लेकिन कारणों को स्वयं समझना कानून में मान्य नहीं है। जो कोई भी अपने अधिकार की अनदेखी करता है, उसे कष्ट सहना ही पड़ता है। ...
>
> 28. विलंब और लापरवाही के तथ्य से अनभिज्ञ रहना और राहत प्रदान करना सभी स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है और यहाँ तक कि विवेकाधिकार की अवधारणा को भी दूर-दूर तक आकर्षित नहीं करता। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि यह उन सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता जहाँ मौलिक अधिकारों की कुछ श्रेणियों का उल्लंघन होता है। लेकिन, पदोन्नति लाभ प्राप्त करने के एक पुराने दावे पर न्यायाधिकरण द्वारा निश्चित रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।"

इसमें शांति का तत्व होना चाहिए और एक पुराने दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

xxxx xxxx xxxx xxxx

24. वर्तमान मामले में, न्यायालय का रिकॉर्ड इंगित करता है कि अतिरिक्त प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें करते समय चयन समिति ने उम्मीदवारों के प्रदर्शन, उनके रिकॉर्ड के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञों की राय को भी ध्यान में रखा था। 12-9-2005 की बैठक के मिनट्स से संकेत मिलता है कि तकनीकी विशेषज्ञों के विचारों पर विचार किया गया था। बारह साल पहले जो हुआ उसका पुनर्मूल्यांकन करना न तो संभव होगा और न ही उचित होगा। 1997 का नीतिगत निर्णय इंगित करता है कि चयन समिति के सभी सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दी गई ग्रेडिंग को चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाना चाहिए और चयन समिति के सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दी गई ग्रेडिंग/अंकों के आधार पर अंतिम चयन "किया जा सकता है"। 2005 में गठित चयन समिति ने चयन और चयनित उम्मीदवारों की परस्पर रैंकिंग के मुद्दे पर विचार किया। अतिरिक्त प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के समय, उनके योग्यता क्रम के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिश करते समय, चयन समिति ने उम्मीदवारों के प्रदर्शन, उनके रिकॉर्ड और विशेषज्ञों की राय सहित प्रासंगिक मामलों पर उचित ध्यान दिया था। इसलिए, जो रैंकिंग दी गई है, उसे 1997 के नीतिगत निर्णय का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं और चौथे प्रतिवादी के अतिरिक्त प्रोफेसर के रूप में चयन के बारह वर्षों से अधिक समय बाद, वरिष्ठता की स्थिति को अस्थिर करना अन्याय होगा। उसके बाद भी, जब उनमें से प्रत्येक को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया है, तो चौथे प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं से उच्च रैंक दी गई है।

25. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राहत प्रदान करने से याचिकाकर्ताओं और चौथे प्रतिवादी के बीच अतिरिक्त प्रोफेसरों के रूप में नियुक्ति हेतु चयन समिति की सिफारिश के बारह वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही पारस्परिक वरिष्ठता अस्थिर हो जाएगी। ऐसा नहीं

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

किया जा सकता। विभागीय प्रक्रियाओं में प्रथम याचिकाकर्ता के पक्ष में कुछ विचारों की अभिव्यक्ति ने आशा की एक किरण जगाई होगी। लेकिन यह उस चीज़ को अस्थिर करने का कोई कानूनी आधार नहीं प्रदान कर सकता जो लंबे समय से इस क्षेत्र में व्याप्त है। हम इस उम्मीद के साथ कार्यवाही समाप्त करते हैं कि ये प्रतिष्ठित डॉक्टर बिना किसी द्वेष के एम्स में अपने पेशे को जारी रखेंगे। वरिष्ठता पर हमारा निर्णय किसी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान में उनकी विशिष्ट सेवा का कोई प्रतिबिंब नहीं है।"

5. उपरोक्त सभी निर्णयों के सारांश से जो समान सूत्र और विलक्षण बिंदु उभरता है, वह यह है कि स्थापित वरिष्ठता को अनुचित समय बीत जाने के बाद दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि एक या कुछ कर्मचारियों के कहने पर लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता को बिगाड़ने से अन्य सहकर्मियों की स्थापित वरिष्ठता और निहित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह कानून एक ठोस तर्क और रिट स्वीकार करने के प्रथम सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए आराम से सोते रहते हैं, उन्हें वर्षों बाद गहरी नींद से जगाकर प्रतिस्पर्धा में दूसरों की तुलना में बेहतर वरिष्ठता के अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे स्थिति बिगड़ जाए।

6. इस याचिका में शामिल देरी और कुंडी के प्रश्न और मुद्दे को उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट किए गए सिद्धांतों के आधार पर परखने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तारीख और 1982 की वरिष्ठता में रखे गए अन्य समान व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानता था, लेकिन याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 तक चुप्पी साधे रखी और अचानक, 22 वर्षों से अधिक की अत्यधिक देरी के बाद, वह जागा और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए और 18.09.1982 से वरिष्ठता का दावा करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत सीधे तौर पर उन अन्य व्यक्तियों की लंबे समय से स्थापित वरिष्ठता पर प्रभाव डालती है, जिन्हें पदोन्नति दी गई है और इसे 42 वर्षों से अधिक समय बाद, वर्ष 2024 में 22 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद प्रस्तुत याचिका में अस्थिर करने के लिए बदला नहीं जा सकता है।

7. कानून की यह सुस्थापित प्रस्तावना है कि यदि याचिकाकर्ता की ओर से अत्यधिक विलंब हो और इस विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाए तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने और राहत देने से इनकार कर सकता है। यह कहा गया कि यह नियम कई कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय सामान्यतः असाधारण उपाय के लिए विलंबित उपाय की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इससे भ्रम और सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न होने और अपने साथ नए अन्याय आने की संभावना होती है और यदि अनुचित विलंब के बाद रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तो इससे न केवल कठिनाई और असुविधा उत्पन्न हो सकती है बल्कि तीसरे पक्ष पर अन्याय भी हो सकता है। यह बताया गया कि जब रिट अधिकार क्षेत्र

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

का आह्वान किया जाता है तो इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकारों के सृजन के साथ अस्पष्टीकृत विलंब एक महत्वपूर्ण कारक है जो उच्च न्यायालय के लिए इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने या न करने का निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण होता है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **नादिया जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद बनाम सृष्टिधर बिस्वार मामले में (2007) 12 एससीसी 779** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> 11. वर्तमान मामले में, पैनल 1980 में तैयार किया गया था और याचिकाकर्ताओं ने दिबाकर पाल मामले में आए फैसले के बाद 1989 में अदालत का रुख किया। ऐसे व्यक्तियों को अदालत द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जिन्होंने नौ साल से ज़्यादा समय बीत जाने दिया। राहत देने के मामलों में देरी बहुत महत्वपूर्ण होती है और अदालतें उन व्यक्तियों की मदद नहीं कर सकतीं जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा नौ साल की देरी को माफ़ करने के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

9. उच्चतम न्यायालय ने **जगदीश लाल बनाम हरियाणा राज्य मामले (1997) 6 एससीसी 538** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> 18. इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है, देरी के कारण पक्षकार संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत विवेकाधीन राहत पाने के हकदार नहीं रह जाते।

10. उच्चतम न्यायालय ने **एनडीएमसी बनाम पान सिंह मामले (2007) 9 एससीसी 278** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> 16. मामले का एक और पहलू है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों ने 17 साल बाद रिट याचिका दायर की। उन्होंने लंबे समय तक अपनी शिकायतें नहीं उठाईं। जैसा कि यहाँ देखा गया है, उन्होंने जल्द से जल्द 17 कामगारों के साथ समानता का दावा नहीं किया। उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष राज्य द्वारा किए गए संदर्भ में भी खुद को पक्षकार नहीं बनाया। उनका यह मामला नहीं है कि 1982 के बाद, जिन कर्मचारियों को नियोजित किया गया था या जिनकी भर्ती कट-ऑफ तिथि के बाद हुई थी, उन्हें उक्त वेतनमान प्रदान किया गया है। इसलिए, इतने लंबे समय के बाद, रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता था, भले ही उनकी स्थिति समान हो। यह सामान्य बात है कि विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन लोगों के पक्ष में नहीं किया जा सकता जो लंबे समय के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। न्यायसंगत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए विलंब और लापरवाही प्रासंगिक कारक हैं।

11. अत, वर्तमान रिट याचिका में विलम्ब और विलंब है और केवल इसी आधार पर इसे खारिज किया जाना उचित है।

12. उपरोक्त सभी कारणों से, रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

13. अन्य सभी आवेदन, यदि कोई लंबित हों, भी खारिज किए जाते हैं।

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)

(अनूप कुमार ढांड), जे

आयुष शर्मा/185

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:35:56 बजे डाउनलोड किया गया)